पर्यावरण संबंधी दो बड़ी वैश्विक चिंता

साभार : पायनियर
09 सितंबर, 2017

आर.के. पचौरी
(पूर्व अध्यक्ष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल, 2002-15)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यूजीलैंड, जो दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्रों में से एक है, पीस फाउंडेशन नामक एक लाभकारी संगठन पर बेहतर रूप से काम कर रहा। जो भी यहाँ काम करते हैं, वे अपने उद्देश्य के लिए काफी प्रतिबद्ध है, उनकी एक समर्पित टीम है, जो न केवल न्यूजीलैंड के सभी उम्र के लोगों के नागरिकों के बीच शांति स्थापित करने के लिए समर्पित है, बल्कि दूसरे अन्य देशों में भी अपनी पहुंच और अपने उद्देश्य को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 के लिए उनकी योजनाओं में, जहाँ ये संगठन वर्तमान में विश्व के समक्ष दो सबसे बड़ी चिंताओं अर्थात् परमाणु हथियार और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं।

यद्यपि एक अनुस्मारक आवश्यक था, पिछले कुछ दिनों के विकास ने हमें स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये दोनों समस्या वास्तव में सबसे बड़ा जोखिम हैं जिसका प्रभाव हमारे ग्रह पर मानव समाज और सभी प्रकार के जीवन पर पड़ेगा। टेक्सास में और साथ ही बांग्लादेश और दक्षिण एशिया में आई बाढ़, जहाँ बाढ़ के विकराल रूप और गंभीरता के बावजूद इस समस्या पर मीडिया द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। साथ ही, उत्तरी कोरिया द्वारा सभी देशों द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद परमाणु परीक्षण किया जाता रहा है, जहाँ हाल ही में इसने एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है और जापान के उत्तरी भाग पर एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो आने वाले गंभीर चिंताओं को दर्शाता है और यह भी बताता है कि हम कैसे धीरे-धीरे परमाणु आपदा के करीब जा रहे हैं।

वैज्ञानिक रूप से, मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन कोई एकल घटना नहीं हो सकती है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी) पर अंतर-सरकारी पैनल के पांचवें आकलन रिपोर्ट (एआर 5) ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस समस्या की आवृत्ति और तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक वर्षा घटनाओं की आईपीसीसी एआर 5 की टिप्पणियों में से एक में यह भी कहा गया है कि निश्चित रूप से 1970 के बाद से उत्तर अटलांटिक में तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गतिविधि बढ़ गई है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (एसआरईएक्स) को उन्नत करने के लिए चरम घटनाओं और आपदाओं के जोखिम का प्रबंधन नामक एक विशेष रिपोर्ट में आईपीसीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संभावना है कि भारी वर्षा की आवृत्ति या भारी बारिश का कुल अनुपात 21 वीं सदी में बढ़ेगा। इससे दुनिया के कई क्षेत्र, विशेष रूप से उच्च अक्षांश और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और सर्दियों में उत्तरी मध्य अक्षांश क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ साथ भारी वर्षा में काफी वृद्धि हुई है, जिसकी संभावना ग्रीन हाउस गैस और निरंतर ग्लोबल वार्मिंग के कारण और अधिक बढ़ गयी है। साथ ही इसकी भी संभावना बढ़ गयी है कि कुछ क्षेत्रों में कुल वर्षा में अनुमानित कमी के बावजूद भारी वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है।

फिर भी, अमरीका जैसे शक्तिशाली देश का नेतृत्व किसी धोखे से कम नहीं लगता। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका ट्रम्प शासन में जलवायु परिवर्तन की समस्या को नहीं मानता, यहां तक कि यह आईपीसीसी की धारणा को भी यह गलत मानता है, जिनकी रिपोर्टों को दुनिया के सभी सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण जांच के जरिए अनुमोदित किया गया है। देखा जाये तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अपने वैज्ञानिक निकायों और अकादमियों को नजरंदाज कर दिया है।

अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित निकायों द्वारा हर प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन पृथ्वी के जलवायु पर मानव कार्यों के प्रभाव के निर्विवाद साक्ष्य को दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े भारी आर्थिक नुकसान पर अपनी आँखों को बंद कर लेना और ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने के लिए संसाधनों का एक छोटा अंश भी आवंटित करने से इनकार करना निश्चित रूप से चकरा देने वाला एक आर्थिक दृष्टिकोण।

नतीजतन, हमारा वैश्विक समुदाय, अमेरिकी लोगों सहित बड़े पैमाने पर मानवीय पीड़ा, विनाश और भारी आर्थिक नुकसान को उजागर कर रहे हैं। यह वास्तव में ऊर्जा के ऊंचे स्तरों और ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के उपयोग में निवेश करने के आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हाल के वर्षों में इस समस्या के इक्विटी आयामों को चतुराई से जलवायु परिवर्तन पर बहस में तब्दील कर दिया गया है जिसमें विकसित दुनिया के मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों का एक बड़ा हाथ था। मीडिया कवरेज और इस विषय पर विश्लेषण करने पर दो देशों के नाम सामने आते हैं- एक चीन और दूसरा भारत, जो भविष्य में ऊर्जा के उपभोग का सबसे बड़े हिस्सेदार है। वास्तविकता यह है कि हम जो देख रहे हैं, वह जीएचजी की एकाग्रता में बढ़ोतरी का प्रभाव है, जिसमें विकासशील देशों का हिस्सा कम है। एकाग्रता के स्तर में यह वृद्धि औद्योगीकरण की शुरुआत के बाद से जीएचजी के संचयी उत्सर्जन का परिणाम है, जिसके लिए विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी माना जाता है। और अगर हम आज भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखे तो विकासशील देश औद्योगिक देशों में मौजूदा स्तरों से काफी नीचे हैं। जलवायु परिवर्तन पर मानवीय प्रभाव जीएचजी की एकाग्रता में वृद्धि का एक रूप है।

बेशक, इसे सीमित करने के लिए, हमें अब और भविष्य में उत्सर्जन में हो रहे तेजी को कम करने की आवश्यकता है। हांलाकि, इस वजह से एक और समस्या का निर्माण हो जाता है कि कौन देश अपने मौजूदा उत्सर्जनों में कितनी कटौती करेगा। जाहिर है, विकसित

देश अपने उच्च स्तर की ऊर्जा प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन के साथ, कटौती के लिए प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन का एक और असमान पहलू और इसका प्रभाव यह है कि यह तबाही कमजोर और गरीब समाजों को अधिक नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर संकट की स्थिति में राहत और बचाव की सुविधा के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और बुनियादी ढांचे की कमी का कारण है। फिर भी, विकासशील देश उन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसका वे सामना करते हैं। बांग्लादेश, जो आवर्ती बाढ़ से ग्रस्त है, को इस वर्ष लगभग 2.8 मिलियन लोगों को भोजन और अन्य सहायता प्रदान करनी पड़ रही है। दक्षिण एशिया ने पूरे क्षेत्र में गंभीर बाढ़ का सामना किया है, वो भी उस वक्त जब कई बार वर्षा की उच्च स्तर की उम्मीद नहीं रहती है।

निश्चित रूप से वर्ष 2005 के उस दिन को भूलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, जब लगातार 24 घंटों तक मुंबई शहर में लगभग एक मीटर बारिश हुई थी, जिसने पूरे महानगर और जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। दुर्भाग्य से, कई शहर और शहरी क्षेत्र आम तौर पर आपदाओं और जलवायु संबंधित चरम घटनाओं से निपटने के लिए अभी तक सुसज्जित नहीं हुए हैं।

यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश थे, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह घोषणा किया था कि बातचीत के लिए अमेरिका का जीवन मार्ग नहीं था। लेकिन अब इस समस्या के बारे में अधिक जागरूकता दिखानी पड़ेगी और अमेरिका से यह प्रश्न पूछने का वक्त आ गया है कि क्या अमेरिकी समाज वास्तव में तूफान कैटरीना, सैंडी, हार्वे और अब इरमा की अशुभ अगुवाई की वजह से जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक वास्तविकता पर बहस शुरू कर सकता है? और क्या वैश्विक समुदाय परमाणु नि:शस्त्रीकरण के गंभीर मुद्दे को सुलझा पायेगी? कुछ आतंकवादी समूह क्रूड परमाणु हथियारों के साथ आते है, जिसके कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि उत्तर कोरिया नकदी या अन्य विचारों के बदले में इसकी जानकारी आतंकवादियों को देने के लिए तैयार हो जाये। यह समय है कि न्यूजीलैंड में पीस फाउंडेशन की आवाज इस ग्रह पर सभी को सुनाई दे।

संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया तथा क्षमता निर्माण करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा "आपदा प्रबंधन अधिनियम" के माध्यम से की गई थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

शहरी बाढ़ पर जारी दिशा-निर्देश

- राष्ट्रीय स्तर और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर शहरी बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए सार्वभौमिक तकनीकी केंद्र की स्थापना करना।
- भारतीय मौसम विभाग एक 'स्थानीय नेटवर्क सेल' स्थापित करेगा।
- देश में डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क का सामरिक विस्तार, जिसके जरिये अधिकतम संभावित लीड-टाइम के साथ सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करना।
- शहरी बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना।
- स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन का आधार जल ग्रहण क्षेत्र होगा।
- कंटूर मैपिंग 0.2 - 0.5 मीटर समोच्च अंतराल पर तैयार किया जायेगा।
- मौजूदा स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी।
- मानसून से पूर्व नालियों के अवसादन की सफाई हर साल 31 मार्च से पहले कर लिया जायेगा।
- प्रत्येक इमारत में भवन उपयोगिता के अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल संचयन होगा।
- गरीब लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराकर नालियों और बाढ़ के मैदानों पर व्याप्त अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा।
- जागरूकता निर्माण में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

संभावित प्रश्न

परमाणु हथियार और जलवायु परिवर्तन आज समाज के लिए सबसे बड़ा जोखिम और चिंता का विषय है। जो इस बात से हमे अवगत कराता है कि पीस (peace) फाउंडेशन इन चिंताओं पर केंद्रित है और इसकी आवाज पूरे विश्व को सुननी चाहिए।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World